

संपादकीय

खाई में गिरता लोकतंत्र

लोकतंत्र सूचकांक की 2020 की वैश्विक रैंकिंग में भारत अब 6.61 अंकों के साथ दो पायदान लुढ़कते हुए 53वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत दुनिया के ऊंचे 52 देशों में शामर है, जहाँ उस सूचकांक के द्विसाब से त्रिपूर्ण लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र में भूल-चूक पहली बार दिखलाई गई होती तो उभे दब बचती कि शायद इसमें अगले साल कोई सुधार होगा। लेकिन भारत में लोकतंत्र लगातार कमजोर ही हो रहा है। पिछले साल ज्यू-क्सीपी में लिया गया फैसला, सीएए, एपआरसी आदि के कारण देश में जो माहौल बना, उन बजट से इस सूचकांक में भारत के लोकतंत्र को महज 6.90 अंक मिले थे। तब हम 51वें स्थान पर थे। 2018 में भारत के पास 7.23 अंक थे। इन आंकड़ों से साफ दिखाई दे रहा है कि लोकतंत्र को संभाल पाने में केंद्र सरकार नाकाम रहा। देश में लोकतंत्र ही रही है। एसी बातें बार-बार कहने से हालात नहीं बदलते, बल्कि उनके लिए उन खामियों को दूर करना होगा, जिनकी बजाए से बहारे लोकतंत्र को त्रिपूर्ण बताया जा रहा है। पिछला पूरा साल आंदोलन की भेंट चढ़ गया और रही-सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी, जिसमें लोकडउन की सख्ती के नाम पर नारायण अधिकारों को लाशिए पर धक्काला गया। दो गज की दूरी का नियम लोगों को एक उड़ान होने से रोकता रहा, जबकि उसी दौरान राजनीतिक रैलियां और सभाएं पूर्ववर्त चलती रहीं। जम्मू-कश्मीर में विशेष स्थिति ही खस्त नहीं हुई, मौतिन अधिकार भी दांव लग गए। लंबे वक्त इंटरनेट पालाय, मौदियों विषय पर कारबाई जैसे कारों से लोकतंत्र को बिराम किया जाता रहा। अब देश की राजनीति दिखते ही दो माह से वैयंगी ही हालात बन गए हैं। सरकार एक ओर किसानों से बात करती है, दूसरी ओर उनके दमन के लिए अपनी शक्ति का बेजाए।

बैंकिंग, कौल तुकवाना, सड़क खुदवाना, सीमाओं पर दुश्मन को रोकने के लिए काम आने वाली कंटीली बाड़ लगाने जैसे काम किसी नजरिए से लोकतांत्रिक नहीं कहे जा सकते। लोकतंत्र अपने नागरिकों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार देता है और किसान दो माह से यही कर रहे हैं। जब हम तरह के कदमों के अंतराल व्याप्ति स्तर पर आलोचना होती तो विदेश मंत्रालय सफाई देने के लिए आगे आगे आया। गोदी मीडिया के बाद अब गोदी कलानामों और लालाडियों की फैज भी सरकार के लिए तैयार हो गई है। ये फैजें विटर पर उन अंतर्राष्ट्रीय विस्तरों का विरोध कर रही हैं, जो किसान आंदोलन के समर्थन में आवाज उठ रही हैं। इसे भारत की अंतरिक मसल बताया जा रहा है, देश को एक जुट रहने की अपील की जा रही है। क्या वार्कइ हम इनके कमजोर देश हैं कि कुछ लोगों के द्वारा से हमारी एक जुटा पर खतरा हो सकता है। किसी फिल्म या फिल्म के शीर्षक का या वेबसीरीज का या पोस्टर से हमरे धर्म को खतरा होने लगता है, किसी विदेशी हस्तियों की टिप्पणियों से हम असुरक्षित महसूस करने लगते हैं, किसी किसी लोखक, कलाकार का प्रत्रकार की कही बात से देश की सुरक्षा खोने पे डूँगी जाती है। किसी घेरेलू महिलाओं के सड़कों पर खतरा होने के लिए बालों को डर लगाने लगता है। अगर इनी सारी कमजोरियां हमें एक साथ भयभीत कर रही हैं, तो पिर आत्मसंरक्षण की जरूरत है कि अखिर ये कैसा नया भारत हमने बना लिया जा सकता है। केंद्र सरकार के कुछ फैसले और कार्रवाईयां लोकतंत्र के लिए घाटक साबित हो रही हैं, वहीं अब बिहार सरकार ने यह करियर के बाद अब गोदी कलानामों और लालाडियों की फैज भी सरकार के लिए तैयार हो गई है। ये फैजें विटर पर उन अंतर्राष्ट्रीय विस्तरों का विरोध कर रही हैं, जो किसान आंदोलन के बारे में आवाज उठ रही हैं। देश को एक जुट रहने की अपील की जा रही है।

हाइड्रोजन इकॉनॉमी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल में पेश बजट में हाइड्रोजन इकॉनॉमी पर खाया ध्यान दिया है। इस संबंध में उन्होंने न केवल ग्रीन हाइड्रोजन पर काम करने के लिए गतिशील होने का एनारोनी मिशन का जिक्र किया, बल्कि इस में ढाई हजार करोड़ रुपये का व्यावहारिक विकल्प के रूप में स्थिकाकरण करना संभव नहीं हो पा रहा। पहली दिक्कत सुझा की है। अत्यधिक जलवायनशील होने की बहुत हो से हाइड्रोजन अपने साथ खतरनाक कर रही है। इसका बहल से अधिकतम खतरण से है जो पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस जैसे प्रदूषणकारी ईंधों के बजाय हाइड्रोजन जैसे जीरो पॉल्यूशन फ्लूट पर चलती है। वैसे तो इस पर काम काफी पहले से चल रहा है, पर दो-तीन ऐसी दिक्कतों अभी कायम हैं जिनकी बजाए से हाइड्रोजन को व्यावहारिक विकल्प के रूप में स्थिकाकरण करना संभव नहीं हो पा रहा। हालांकि सुझी की बात को जलवायनशील होने की बहुत कमजोर हो रही है।

इसका बहल से अधिकतम खतरण से है जो पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस जैसे प्रदूषणकारी ईंधों के बजाय हाइड्रोजन जैसे जीरो पॉल्यूशन फ्लूट पर चलती है। वैसे तो इस पर काम काफी पहले से चल रहा है, पर दो-तीन ऐसी दिक्कतों अभी कायम हैं जिनकी बजाए से हाइड्रोजन को व्यावहारिक विकल्प के रूप में स्थिकाकरण करना संभव नहीं हो पा रहा। हालांकि सुझी की बात को जलवायनशील होने की बहुत कमजोर हो रही है।

इसका बहल से अधिकतम खतरण से है जो पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस जैसे प्रदूषणकारी ईंधों के बजाय हाइड्रोजन जैसे जीरो पॉल्यूशन फ्लूट पर चलती है। वैसे तो इस पर काम काफी पहले से चल रहा है, पर दो-तीन ऐसी दिक्कतों अभी कायम हैं जिनकी बजाए से हाइड्रोजन को व्यावहारिक विकल्प के रूप में स्थिकाकरण करना संभव नहीं हो पा रहा। हालांकि सुझी की बात को जलवायनशील होने की बहुत कमजोर हो रही है।

इसका बहल से अधिकतम खतरण से है जो पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस जैसे प्रदूषणकारी ईंधों के बजाय हाइड्रोजन जैसे जीरो पॉल्यूशन फ्लूट पर चलती है। वैसे तो इस पर काम काफी पहले से चल रहा है, पर दो-तीन ऐसी दिक्कतों अभी कायम हैं जिनकी बजाए से हाइड्रोजन को व्यावहारिक विकल्प के रूप में स्थिकाकरण करना संभव नहीं हो पा रहा। हालांकि सुझी की बात को जलवायनशील होने की बहुत कमजोर हो रही है।

इसका बहल से अधिकतम खतरण से है जो पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस जैसे प्रदूषणकारी ईंधों के बजाय हाइड्रोजन जैसे जीरो पॉल्यूशन फ्लूट पर चलती है। वैसे तो इस पर काम काफी पहले से चल रहा है, पर दो-तीन ऐसी दिक्कतों अभी कायम हैं जिनकी बजाए से हाइड्रोजन को व्यावहारिक विकल्प के रूप में स्थिकाकरण करना संभव नहीं हो पा रहा। हालांकि सुझी की बात को जलवायनशील होने की बहुत कमजोर हो रही है।

इसका बहल से अधिकतम खतरण से है जो पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस जैसे प्रदूषणकारी ईंधों के बजाय हाइड्रोजन जैसे जीरो पॉल्यूशन फ्लूट पर चलती है। वैसे तो इस पर काम काफी पहले से चल रहा है, पर दो-तीन ऐसी दिक्कतों अभी कायम हैं जिनकी बजाए से हाइड्रोजन को व्यावहारिक विकल्प के रूप में स्थिकाकरण करना संभव नहीं हो पा रहा। हालांकि सुझी की बात को जलवायनशील होने की बहुत कमजोर हो रही है।

इसका बहल से अधिकतम खतरण से है जो पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस जैसे प्रदूषणकारी ईंधों के बजाय हाइड्रोजन जैसे जीरो पॉल्यूशन फ्लूट पर चलती है। वैसे तो इस पर काम काफी पहले से चल रहा है, पर दो-तीन ऐसी दिक्कतों अभी कायम हैं जिनकी बजाए से हाइड्रोजन को व्यावहारिक विकल्प के रूप में स्थिकाकरण करना संभव नहीं हो पा रहा। हालांकि सुझी की बात को जलवायनशील होने की बहुत कमजोर हो रही है।

इसका बहल से अधिकतम खतरण से है जो पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस जैसे प्रदूषणकारी ईंधों के बजाय हाइड्रोजन जैसे जीरो पॉल्यूशन फ्लूट पर चलती है। वैसे तो इस पर काम काफी पहले से चल रहा है, पर दो-तीन ऐसी दिक्कतों अभी कायम हैं जिनकी बजाए से हाइड्रोजन को व्यावहारिक विकल्प के रूप में स्थिकाकरण करना संभव नहीं हो पा रहा। हालांकि सुझी की बात को जलवायनशील होने की बहुत कमजोर हो रही है।

इसका बहल से अधिकतम खतरण से है जो पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस जैसे प्रदूषणकारी ईंधों के बजाय हाइड्रोजन जैसे जीरो पॉल्यूशन फ्लूट पर चलती है। वैसे तो इस पर काम काफी पहले से चल रहा है, पर दो-तीन ऐसी दिक्कतों अभी कायम हैं जिनकी बजाए से हाइड्रोजन को व्यावहारिक विकल्प के रूप में स्थिकाकरण करना संभव नहीं हो पा रहा। हालांकि सुझी की बात को जलवायनशील होने की बहुत कमजोर हो रही है।

इसका बहल से अधिकतम खतरण से है जो पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस जैसे प्रदूषणकारी ईंधों के बजाय हाइड्रोजन जैसे जीरो पॉल्यूशन फ्लूट पर चलती है। वैसे तो इस पर काम काफी पहले से चल रहा है, पर दो-तीन ऐसी दिक्कतों अभी कायम हैं जिनकी बजाए से हाइड्रोजन को व्यावहारिक विकल्प के रूप में स्थिकाकरण करना संभव नहीं हो पा रहा। हालांकि सुझी की बात को जलवायनशील होने की बहुत कमजोर हो रही है।

इसका बहल से अधिकतम खतरण से है जो पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस जैसे प्रदूषणकारी ईंधों के बजाय हाइड्रोजन जैसे जीरो पॉल्यूशन फ्लूट पर चलती है। वैसे तो इस पर काम काफी पहले से चल रहा है, पर दो-तीन ऐसी दिक्कतों अभी कायम हैं जिनकी बजाए से हाइड्रोजन को व्यावहारिक विकल्प के रूप में स्थिकाकरण करना संभव नहीं हो पा रहा। हालांकि सुझी की बात को जलवायनशील होने की बहुत कमजोर हो रही है।

इसका बहल से अधिकतम खतरण से है जो पेट्रोल, ड

